प्रेस विज्ञप्ति

30 नवंबर, 2017

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

'प्राईवेट बिजली खरीद' के माध्यम से चार प्राईवेट बिजली कंपनियों को मुनाफा कमवाने के तथ्यों से एक व्यापक **'बिजली खरीद घोटाले'** की बू आ रही है। परिणाम भुगत रहे हैं, 6.5 करोड़ गुजराती, जिन्हें न तो पूरी बिजली मिल रही और उल्टा महंगी बिजली दरों ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है।

लगता है कि गुजरात की भाजपा सरकार का नारा है,

'प्राईवेट कंपनियों की जेबें भर दी भारी, बिलों का झटका भुगते गुजरात की जनता सारी!!'

दावा – गुजरात 'बिजली सरप्लस' प्रांत है।

सच्चाई – गुजरात सरकार के पॉवर प्लांट की उत्पादन क्षमता 8,641 मेगावॉट होने के बावजूद, चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले तीन साल से उनकी उत्पादन क्षमता मात्र 33 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक सिकुड़ गई है।

फायदा किसको – केवल चार प्राईवेट बिजली कंपनियों को – यानि अडानी, एस्सार, टाटा व चाईना लाईट पॉवर – जिनसे गुजरात के लोगों की कीमत पर महंगी बिजली खरीदी जा रही है। नतीजा– **सरकार का पैसा लुटाओ, जनता को कर्जदार बनाओ और प्राईवेट बिजली कंपनियों को मुनाफा कमवाओ।**

मुनाफाखोरी, महंगी बिजली व गुजरात की जनता को हो रहे नुकसान की तथ्यात्मक सच्चाई

1. **अचरज की बात है कि साल 2002–2016 के बीच** (श्री नरेंद्र मोदी, 2002–14 तक मुख्यमंत्री थे) **गुजरात सरकार ने चार प्राईवेट बिजली कंपनियों से ₹62,549 करोड़ की अप्रत्याशित बिजली खरीद कर डाली।** शायद देश के किसी भी गुजरात जितने बड़े राज्य द्वारा सरकार के खजाने से खरीदी गई यह सबसे बड़ी बिजली खरीद है।
2. कमाल की बात तो यह है कि 'क्रोनी कैपिटलिज़्म' (सहचर पूंजीवाद) का प्रचार, प्रसार व बढ़ावा देते हुए भाजपा सरकार ने सिर्फ पिछले तीन सालों में (2013–14 से 2015–16) चार प्राईवेट बिजली कंपनियों से ₹26,195 करोड़ की बिजली खरीद कर डाली। कृपया चार्ट देखें :–

Year	Power Purchased (in crores)			
	Adani	ESSAR	Tata	China Light Power
2013-14	3471	1574	2551	612
2014-15	3583	1717	2946	669
2015-16	3842	1551	2994	685
Total	**10,896 crore**	**4,842 crore**	**8,491 crore**	**1,966 crore**

3. आश्चर्य की बात यह भी है कि एक तरफ तो गुजरात के लोगों का पैसा लुटाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ गुजरात सरकार के बिजली प्लांट मात्र 33 प्रतिशत से 38 प्रतिशत बिजली उत्पादन की कर रहे थे। कृपया चार्ट देखें :–

Year	Production Capacity in Mega Watts	Electricity Produced Million Units	Percentage of Load Factor
2013-2014	6712	18518	33%
2014-2015	7765	22899	35%
2015-2016	8641	21844	38%

अजीब बात यह है कि 8,641 मेगावॉट की उत्पादन क्षमता होने के बावजूद, गुजरात सरकार के बिजली प्लांटों से गुजरात के लोगों को मात्र 3,283 मेगावॉट बिजली ही मिल पा रही है। यदि इसके मुकाबले 22 साल पहले मुड़कर देखें, तो कांग्रेस शासन में गुजरात सरकार के बिजली प्लांट दोगुनी अधिक क्षमता पर काम कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर 1991–92, 1992–93 व 1993–94 में कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी बिजली प्लांटों की उत्पादन क्षमता क्रमशः 57 प्रतिशत, 61.6 प्रतिशत व 60.4 प्रतिशत थी।

साल 1995 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, तो गुजरात सरकार के बिजली प्लांट की उत्पादन क्षमता 4,345 मेगावॉट थी। अगर 22 साल बाद सरकारी बिजली प्लांट से लोगों को उपलब्ध होने वाली बिजली का आंकलन करें, तो हम यह पाएंगे कि आज की सरकारी बिजली उपक्रमों से मिल रही बिजली 22 साल पहले की बिजली उत्पादन क्षमता से भी कम है। **यह साबित करता है कि किस प्रकार भाजपा सरकार द्वारा सरकारी बिजली उपक्रमों व उसके बुनियादी ढांचे को एक षडयंत्र के तहत खोखला कर दिया गया है।**

4. चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने निजी बिजली कंपनियों से ₹24.67 प्रति यूनिट की अनापशनाप दरों पर बिजली खरीदी, जबकि उसी समय भारत सरकार के एनटीपीसी द्वारा गुजरात को ₹2.88–₹3.17 प्रतियूनिट पर बिजली दी गई। कृपया चार्ट देखें :–

चाईना लाईट एवं पॉवर इंडिया प्रा. लि. से खरीदी गई बिजली :–

Year	Power Purchased in Million Units	Expenditure In Crores	Rate paid Per Unit
2012-13	1368	Rs.1116/-	Rs.8.15
2013-14	248	Rs.612/-	Rs.24.67
2014-15	283	Rs.669/-	Rs.23.63
2015-16	874	Rs.685/-	Rs.7.83

एनटीपीसी से खरीदी गई बिजली :–

Year	Power Purchased in Million Units	Expenditure in Crores	Rate paid Per Unit
2012-13	15322	Rs.4033/-	Rs.2.63
2013-14	13920	Rs.4416/-	Rs.3.17
2014-15	16364	Rs.5135/-	Rs.3.13
2015-16	17484	Rs.5036/-	Rs.2.88

इसके विपरीत, तत्कालीन केंद्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बिजली दर नीति, 2006 के मुताबिक केवल कंपटिटिव बिड्स के अनुसार ही बिजली की खरीद की जा सकती थी। निजी कंपनी व सरकारी कंपनी द्वारा बिजली की दरों का भारी अंतर अपने आप असलियत को जगजाहिर करता है।

<u>एक तरफ तो साधारण गुजराती को महंगी बिजली की दरों का झटका लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वित्तीय कुप्रबंधन, घालमेल व घोटाला साफ है। इसीलिए :–</u>

22 सालों का हिसाब,

गुजरात मांगे जवाब!